RNI No: UPHIN/2023/86769

www.swarajindianews.com

swarajindia2023@gmail.c swarajindi- swarajindi-

सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

मूल्यः ₹ 02

अयोध्या : नगर निगम में टेंडर ठगी का बड़ा खेल उजागर

» Pg10

कानपुर,बुधवार , 10 सितंबर 2025
वर्षः 02, अंकः 238, पृष्ठः 8+4

इनसाइड अवैध निर्माण पर कार्रवाईः केडीए ने अवैध निर्माण तोड़ा » Pg 3

नेपाल के बाद फ्रांस में भी तख्ता पलट!

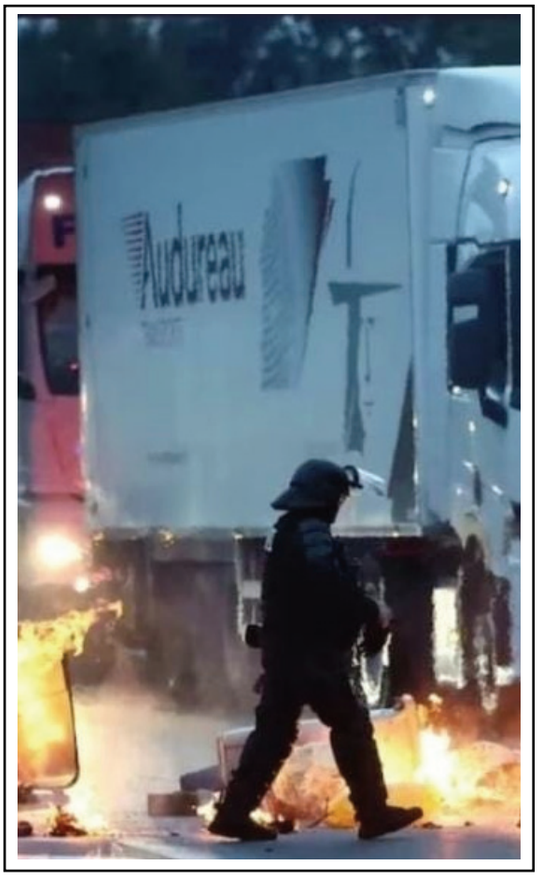

फ्रांस में 'ब्लॉक एवरीथिंग' आंदोलन से हड़कंप,मैक्रों की सत्ता पर गहराया संकट, यूरोप के लिए भी चेतावनी की घंटी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

पेरिस/नई दिल्ली।

नेपाल की सड़कों पर हालिया राजनीतिक बगावत के बाद अब फ्रांस भी अशांति की आग में झुलस रहा है। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के खिलाफ ब्लॉक एवरीथिंग नामक नए आंदोलन ने बुधवार को पूरे देश को जाम कर दिया। राजधानी पेरिस से लेकर मार्से, लियोन और नांत तक हाईवे ठप, आगजनी और बसों को फूंकने की घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि जनता अब व्यवस्था के खिलाफ खुली बगावत पर उतर आई है।

फ्रांस की संसद पहले ही प्रधानमंत्री फ्रांस्वा बायरू को अविश्वास मत में हरा चुकी है, जिसके बाद मैक्रों को अपने कार्यकाल का पाँचवाँ प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकोर्नू नियुक्त करना पड़ा। यह स्थिति सिर्फ फ्रांस की नहीं, बल्कि पूरे यूरोप की राजनीति की कमजोरी और बढ़ती जन असंतोष की निशानी मानी जा रही है।

ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन का नारा है – अगर सिस्टम काम नहीं करता तो देश की मशीनरी रोक दो। यही वजह है कि हजारों प्रदर्शनकारियों ने सड़कें, हाईवे और परिवहन तंत्र को पंगु बना दिया। सरकार ने हालात काबू में रखने के लिए 80,000 सुरक्षाबलों की तैनाती की है, जिसमें से 6,000 पेरिस में मौजूद हैं। लेकिन यह संख्या भी उग्र होती भीड़ के सामने नाकाफी साबित हो रही है।फ्रांसीसी मीडिया और अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह विद्रोह 2018 के यलो वेस्ट आंदोलन की याद दिला रहा है, जब ईंधन की कीमतों के विरोध ने पूरे यूरोप में राजनीतिक भूचाल ला दिया था। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार आंदोलन की कमान दक्षिणपंथ से निकलकर वामपंथ और अतिवामपंथी ताकतों के हाथ में जा चुकी है।

गृह मंत्री ब्रूनो रेटायो ने स्वीकार किया कि बोर्डो में नकाबपोशों ने हाईवे रोकने की कोशिश की, टूलूज़ में आगजनी से ट्रैफिक ठप हो गया, और पेरिस पुलिस को 75 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतनी गिरफ्तारियां और सुरक्षा बल इस बगावत की आग को थाम पाएंगे?

विशेषज्ञों का मानना है कि यह विद्रोह केवल मैक्रों की सत्ता के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरे यूरोपीय संघ की राजनीतिक स्थिरता पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। यूक्रेन युद्ध, महंगाई और ऊर्जा संकट के बीच अगर फ्रांस जैसा मजबूत लोकतंत्र भी हिल रहा है, तो यूरोप में नई अस्थिरता और कट्टर राजनीति का उभार अब दूर नहीं।

कानपुर के लिए खुशखबरी: स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में मिला 5 वां स्थान

दिल्ली-मुंबई को पछाड़ा, टॉप फाइव में बनाई जगह

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। कभी देश के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाने वाला कानपुर अब अपनी नई पहचान गढ़ रहा है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कानपुर को पांचवां स्थान मिला है।दिल्ली, मुंबई, जयपुर और पटना जैसे बड़े शहरों को पछाड़ते हुए कानपुर टॉप फाइव में शामिल हुआ है। सर्वेक्षण में कानपुर को 192.2 अंक हासिल हुए। इस श्रेणी में पहला स्थान इंदौर, दूसरा जबलपुर और तीसरा स्थान आगरा व सूरत को संयुक्त रूप से मिला। पिछले साल भी कानपुर पांचवें स्थान पर था, लेकिन इस बार उसे बेहतर अंक मिले हैं।

औद्योगिक दबाव और वाहनों के बीच सफाई, हरित पट्टियों व यातायात नियंत्रण से बदली तस्वीर

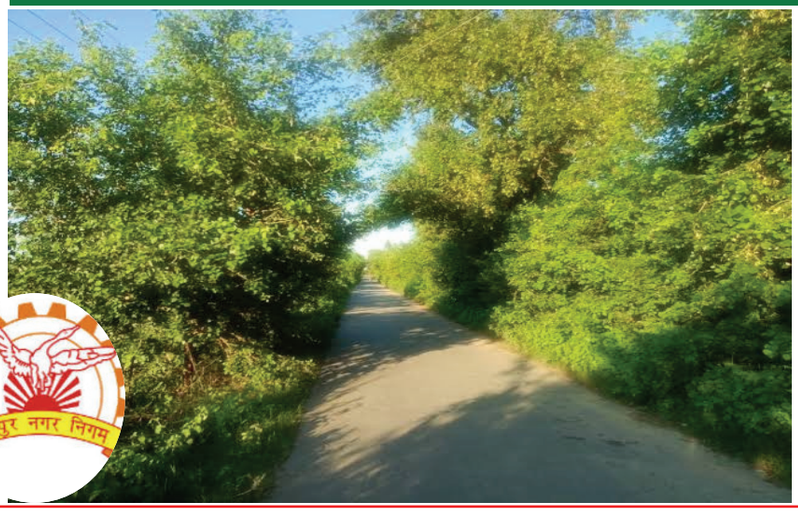

सुधार की दिशा में उठाए गए कदम

नगर निगम और प्रशासन ने पिछले एक साल में कई मोर्चों पर काम किया। प्रमुख सड़कों पर मशीनों से सफाई कर धूल की समस्या पर नियंत्रण पाया गया।

निर्माण कार्यों से निकलने वाली धूल रोकने के लिए सख्ती से नियम लागू किए गए। पुराने कूड़े के ढेरों का निस्तारण हुआ और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुधारा गया।

हरित पट्टियों और वाटिकाओं का विकास किया गया, यातायात नियंत्रण के प्रयास हुए और जाम की समस्या कम करने के उपाय किए गए। उद्योगों में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा दिया गया। इन पहलों का असर साफ दिखाई दिया और शहर की हवा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार दर्ज हुआ।

करकमलों द्वारा

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने किया

109 विकास कार्यों का शिलान्यास

मुख्य संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने हरजेंदर नगर मंडल में 58 सड़कों व यशोदा नगर में 51 सड़कों का शिलान्यास किया। यशोदा नगर के एक गेस्ट हाउस में संपन्न हुए शिलान्यास कार्यक्रम में पार्षदों, मंडल अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ सतीश महाना का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं के स्वागत से अभिभूत सतीश महाना ने उपस्थित क्षेत्रीय जनता को विश्वास दिलाया कि महाराजपुर विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा के रूप में जब तक विकसित नहीं कर लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे।40 वर्षों तक गंगा बैराज योजना राजनीतिक जुमलेबाजी रही थी

अपने संबोधन में पुराने दिनों और कार्य संस्कृति को याद करते हुए सतीश महाना ने बताया कि जब वह वर्ष 1991 में पहली बार छावनी क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बनाए गए और पहली चुनावी सभा में भाषण देने जा रहे थे तो उन्होंने लोगों से पूछा कि मंच पर चढ़कर मैं क्या भाषण दूं ,किन मुद्दों पर बात करूं तो एक सीनियर ने उनसे कहा कि तुम बाकी विषयों पर बोलते हुए यह जरूर बोलना कि अगर मैं विधायक बन गया तो गंगा बैराज का निर्माण कराऊंगा। सतीश महाना ने कहा कि मुझे गंगा बैराज के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं थी और जब तक मैं उनसे यह पूछ पाता कि यह गंगा बैराज है क्या! तब तक मंच से मुझे संबोधन के लिए बुला लिया गया और अपने संबोधन में मैंने क्षेत्र की जनता से यह वादा कर दिया कि अगर मैं चुनाव जीता, विधायक बना तो गंगा बैराज का निर्माण कराऊंगा। उन्होंने कहा जब वह मंच से नीचे उतरे तो जिन महोदय ने उन्हें गंगा बैराज का जिक्र करने की नसीहत दी थी उनसे गंगा बैराज के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा गंगा बैराज कुछ नहीं है पिछले 4 दशक से राजनीतिक मंचों पर इस्तेमाल होने वाला एक जुमला है। उन्होंने लोगों को बताया कि जब आगे चलकर केंद्र में अटल जी की सरकार और राज्य में भाजपा सरकार थी और लालजी टंडन नगर विकास मंत्री बने और स्वयं सतीश महाना नगर विकास राज्य मंत्री बने तब सभी के सहयोग से गंगा बैराज का निर्माण पूरा हो सका।

विकास कार्यों को लेकर पूर्व सांसद पर कटाक्ष और एक कार्यकर्ता के लिए चुटकी

सतीश महाना ने उस समय को याद किया जब वह पहली बार 2012 में

हरजेंदर नगर मंडल में 58 यशोदा नगर मंडल में 51 विकास कार्यों की सौगात

महाराजपुर विधानसभा से चुनाव लड़े थे और क्षेत्र की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उन्होंने कहा जब वह क्षेत्रीय लोगों से उस समय मिले तो उन्होंने एक सांसद की भूरि भूरि प्रशंसा की। लोगों ने कहा उनके समय में यशोदा नगर का बहुत ज्यादा विकास हुआ था। जब उन्होंने पूछा कि क्या विकास कर दिया तो लोग बोले पूरे क्षेत्र में उन्होंने दो सड़कों का निर्माण कराया।इस पर यशोदा नगर मंडल के पूर्व उपाध्यक्ष ने जब सर हिलाकर हामी भरी तो महाना ने कहा कि यह विनीत द्विवेदी जी देखो हामीं भर रहे हैं और यह उन महोदय को अच्छे से जानते हैं। विनीत जी उस समय उन पूर्व सांसद के बहुत निकट सहयोगी हुआ करते थे।

उन्होंने आश्चर्य के साथ कहा बताइए इतने बड़े यशोदा नगर क्षेत्र में दो सड़कों के निर्माण को लोग बहुत बड़ा विकास मान रहे थे जबकि आज यशोदा नगर मंडल में 51 विकास कार्यों का एक साथ शिलान्यास हो रहा है।

सतीश महाना ने डबल इंजन सरकार की नीतियों पर बोलते हुए कहा कि अन्त्योदय सिद्धांत पर चलते हुए भाजपा बिजली, पानी, सड़क व नाली आदि की सुविधा उपलब्ध कराकर आम जनता का जीवन स्तर सुधारने का निरंतर प्रयास कर रही है। सरकार ने जीएसटी की दरों मे भारी कटौती कर आम जनता को बड़ी राहत दी है। जहां एक ओर चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा का क्षेत्र तथा रोजमर्रा की उपयोगी वस्तुओं पर शून्य व 5 प्रतिशत जीएसटी की दरें लागू की हैं। वहीं दूसरी ओर अन्नदाता किसानों के लिए कृषि उपकरणों व कीटनाशक पर जीएसटी केवल 5 प्रतिशत कर दिया गया।

भौंती गौशाला की जमीनों के बंदरबांट पर प्रशासन का बड़ा कदम

हाईकोर्ट में दाखिल होगी कैविएट: जिला प्रशासन

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। अरबों की कीमत वाली कानपुर गोशाला सोसाइटी, भौंती की जमीन को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद अब निर्णायक दौर में पहुंचता दिख रहा है। करीब 164 हेक्टेयर जमीन को सीलिंग एक्ट के तहत अधिग्रहित करते हुए राज्य सरकार के नाम दर्ज किया जा चुका है। अब इसी मामले में जिला प्रशासन ने मण्डलायुक्त की कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है और जल्द ही हाईकोर्ट में भी कैविएट दाखिल की जाएगी।

प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, कैविएट दाखिल करने का मकसद यह है कि यदि इस जमीन से जुड़े किसी भी तरह के आदेश पारित हों तो उससे पहले प्रशासन का पक्ष भी सुना जा सके।

2014 से चल रहा जमीन लूट का विवाद

राज्य सरकार ने कानपुर गोशाला सोसाइटी के पास कानून की तय सीमा से अधिक भूमि होने का मुद्दा उठाया था। इसके बाद तत्कालीन एडीएम कोर्ट ने 19 सितंबर 2014 को कुल 164.684 हेक्टेयर जमीन को राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहित करने का आदेश दिया था।

सोसाइटी ने इस आदेश के खिलाफ मण्डलायुक्त की कोर्ट में अपील दायर की। अपील में सोसाइटी की ओर से यह दलील दी गई थी कि आदेश में जमीन के विभिन्न पहलुओं पर स्पष्टता नहीं है—जैसे कितनी भूमि सिंचित है और कितनी असिंचित, कितनी एक फसली है और कितनी दो फसली, कितनी जमीन पर आबादी या तालाब है, और कितनी जमीन खेती योग्य है। सोसाइटी का तर्क था कि इन बिंदुओं पर विचार किए बिना भूमि का अधिग्रहण अवैध है।

दोबारा सुनवाई, पर आदेश बहाल

मण्डलायुक्त की कोर्ट ने सोसाइटी की आपत्तियों पर गौर करते हुए मामले को एडीएम कोर्ट में दोबारा सुनवाई के लिए भेजा था। इसके बाद सभी पक्षों को सुनने के बाद एडीएम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश को ही बहाल रखा।

एडीएम फाइनेंस विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि इस फैसले के बाद प्रशासन पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है। कमिश्नर कोर्ट में

कैविएट दाखिल की जा चुकी है और हाईकोर्ट में भी जल्द दाखिल होगी, ताकि किसी भी आदेश से पहले सरकार और प्रशासन का पक्ष सुना जा सके।

भौंती स्थित इस भूमि की मौजूदा बाजार कीमत अरबों रुपये बताई जा रही है। यही वजह है कि वर्षों से इस पर सोसाइटी और प्रशासन के बीच कानूनी जंग चल रही है। प्रशासन का दावा है कि कानूनन यह भूमि राज्य सरकार के पास रहनी चाहिए, वहीं सोसाइटी अपने अधिकार बचाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा रही है।

अवैध निर्माण पर कार्रवाई: केडीए ने अवैध निर्माण तोड़ा

» जोन 4 किदवई नगर में एक आवासीय भूखंड पर हुई कार्रवाई

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए किदवई नगर क्षेत्र में स्थित एक आवासीय भूखंड पर भवन गिराने का आदेश जारी किया था। जारी आदेश के अनुसार, प्लाट संख्या 28 व 29, ब्लाक-एन, किदवई नगर पर स्वामी श्रीमती रूची सिंह द्वारा बिना स्वीकृत मानचित्र के अनधिकृत निर्माण किया गया था।

इस मामले में संबंधित पक्ष को सुनवाई का पूरा अवसर दिया गया, लेकिन वह कोई भी ठोस कारण प्रस्तुत करने में असफल रहे।प्राधिकरण की ओर से जारी नोटिस (वाद सं. KDA/z4/ANI/2025/0004040) में कहा गया है कि भवन स्वामी को आदेश की प्राप्ति से 15 दिनों के भीतर स्वयं अवैध निर्माण हटाना होगा, अन्यथा केडीए अपनी ओर से भवन को गिरा देगा और खर्च की वसूली राजस्व के रूप में की जाएगी।

इसी क्रम में जोनल अधिकारी प्रवीण कुमार शर्मा की टीम ने अवैध निर्माण को तोड़ दिया। केडीए की सख्ती से हड़कंप मच गया।

कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी अभय कुमार पांडेय ने स्पष्ट किया है कि शहर की सुंदरता और योजनाबद्ध विकास में बाधा डालने वाले किसी भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

- शुक्लागंज में खतरे के निशान से सिर्फ 81 सेंटीमीटर नीचे
- बिठूर-उन्नाव के 18 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में
- हजारों परिवार छतों व सड़कों पर, राहत शिविरों में शरण
- कानपुर-उन्नाव में गंगा का जलस्तर खतरनाक

बाढ़ का कहर
गंगा के उफान से
दर्जनों गांव जलमग्न

» प्रमुख संवाददाता दैनिक स्वराज इंडिया

कानपुर/उन्नाव। गंगा नदी का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है और हालात अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। नरोरा से गंगा का पानी सीमित रूप से छोड़ा जा रहा है, लेकिन काली नदी, रामगंगा नदी, नून नदी और आसपास की छोटी-छोटी नदियों के उफान के कारण गंगा का स्तर तेज़ी से ऊपर जा रहा है। शुक्लागंज में जलस्तर अब खतरनाक बिंदु 114 मीटर से केवल 81 सेंटीमीटर नीचे रह गया है। यह इस साल का सबसे ऊंचा स्तर है, जिसने लोगों में दहशत फैला दी है। मंगलवार को जलस्तर 113.19 मीटर तक पहुंच गया। इससे न केवल शहरी इलाकों बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी खतरा बढ़ गया है।

परमट मंदिर की सीढ़ियों तक पानी पहुंच चुका है और यदि जलस्तर और बढ़ता है तो गंगा में गिरने वाले नाले ओवरफ्लो होकर आसपास के मोहल्लों में पानी भर देंगे। उन्नाव से कानपुर का संपर्क मार्ग कट चुका है और तीन पुलों से आवागमन रोकना पड़ा है। हजारों लोग रोजमर्रा के कामकाज के लिए जाम और आवाजाही की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। प्रशासन और सिंचाई विभाग के अफसर लगातार गंगा के किनारों पर निगरानी बनाए हुए हैं। गांव-गांव जाकर ग्रामीणों से संपर्क किया जा रहा है ताकि पानी बढ़ने की स्थिति में उन्हें समय रहते सुरक्षित स्थानों पर निकाला जा सके।

गांवों में जलभराव, फसलें और मवेशी संकट में

बिठूर की कटरी पट्टी के 18 गांव पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। घरों में पानी घुसने के बाद 400 से ज्यादा परिवार छतों पर शरण लेने को मजबूर हैं।

सात गांवों के करीब 460 परिवार गंगा बैराज स्थित बाढ़ शिविरों में शरणार्थी जीवन जी रहे हैं। हाईवे पर ही अस्थायी रसोईघर बनाए गए हैं, जहां से धुएं की लपटें उठती दिख रही हैं।

बिजली आपूर्ति बंद होने से रातें अंधेरे में गुजर रही हैं। बच्चे और महिलाएं सबसे ज्यादा परेशानी झेल रहे हैं। स्कूल बंद हो गए हैं और बीमार लोगों को इलाज के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है।खेती-किसानी पर भी बाढ़ का गहरा असर पड़ा है। लौकी, कद्दू, तरोई, बैंगन और अमरूद की 2000 बीघा से ज्यादा की फसल पानी में डूबकर चौपट हो चुकी है। भूसा और चारा भीगने से मवेशियों के सामने भूख का संकट खड़ा हो गया है।

गांवों में चार फीट तक पानी भरने से संपर्क कट चुका है। नाव और ट्रैक्टर ही आवाजाही का सहारा बने हैं। कई समाजसेवी ट्रैक्टर और नाव लगाकर ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रहे हैं और भोजन वितरित कर रहे हैं। लेकिन राहत की व्यवस्था अभी भी जरूरत के हिसाब से नाकाफी है। लोगों का दर्द यह है कि दशकों से बांध बनाने का वादा होता रहा, लेकिन आज तक ठोस काम नहीं हुआ।

उन्नाव और फत्तेपुर चौरासी में भी हालात बिगड़े

उन्नाव जिले में गंगा का पानी 128 किलोमीटर लंबी कटरी पट्टी में तबाही मचा रहा है। गंजमुरादाबाद, बांगरमऊ, फत्तेपुर चौरासी, परियर और गंगाघाट से लेकर बक्सर तक सैकड़ों गांव पानी से घिर चुके हैं। परिषदीय विद्यालय और गो-आश्रय स्थल जलमग्न हो चुके हैं। कई जगह बिजली के खंभे झुक गए हैं और 250 से अधिक गांवों की बिजली आपूर्ति काट दी गई है। बाढ़ राहत शिविरों या सड़क किनारे तिरपाल डालकर लोग जीवन काटने को मजबूर हैं। प्रशासन ने चार राहत शिविर स्थापित किए हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि नावें पर्याप्त नहीं हैं और चिकित्सा सुविधाएं भी समय पर नहीं पहुंच रही हैं।

डीएम गौरांग राठी और एसपी दीपक भूकर ने मंगलवार को फत्तेपुर चौरासी क्षेत्र में सड़क कटान का स्थलीय निरीक्षण किया और सिंचाई विभाग व पीडब्ल्यूडी को आपात कदम उठाने के निर्देश दिए। दूलीखेड़ा, मंझा और धरमपुर जैसे गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ठप हैं और ग्रामीण वायरल बुखार की चपेट में आ रहे हैं। मजबूर होकर लोग प्राइवेट चिकित्सकों का सहारा ले रहे हैं। दूसरी ओर, फसलें डूबने से किसानों का नुकसान कई गुना बढ़ गया है। अब बेसहारा मवेशियों का झुंड बचे हुए खेतों में घुसकर मक्का, धान और उड़द जैसी फसलों को भी चौपट कर रहा है।पाटन-बीघापुर क्षेत्र के गांवों में हालात और भयावह हो चुके हैं। दूलीखेड़ा ग्राम पंचायत पानी से पूरी तरह घिरी हुई है। गांवों को जोड़ने वाले सभी मार्ग डूब चुके हैं। लोग ऊंचे स्थानों पर तिरपाल डालकर शरण ले रहे हैं। वहीं, 33/11 विद्युत उपकेंद्र में पानी घुसने से 250 गांवों की आपूर्ति बंद कर दी गई है। इससे लोग अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल यही हाल होता है और सरकार के दावे केवल कागजों तक ही सीमित रहते हैं।

सम्पादकीय

कमियां दूर कर लाभ का हो विस्तार

इसमें दो राय नहीं कि पिछले एक दशक में प्रौद्योगिकी ने आम भारतीय के जीवन को सहज-सरल बनाने में निर्णायक भूमिका निभायी है। आज तमाम तरह की सुविधाओं को हासिल करने के लिये उसे दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। अनेक सेवाएं एक क्लिक के साथ उसकी मुट्ठी में होती हैं। दरअसल, डिजिटल इंडिया की महत्वाकांक्षी पहल नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। जिसका मकसद रोजाना व्यवहार में सामने आने वाली जटिलताओं को दूर करके जीवन को आसान बनाना था। निस्संदेह, पिछले एक दशक में इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने कई प्रकार से नागरिकों को सशक्त बनाने में निर्णायक भूमिका निभायी है। विशेष रूप से डिजिटल भुगतान आज पूरे देश में अपरिहार्य हो गए हैं। इससे जुड़े आंकड़े पूरी दुनिया को चौंका रहे हैं। इस वर्ष अप्रैल में लगभग 25 लाख करोड़ रुपये के यूपीआई लेन-देन किए गए हैं।

इन यूपीआई लेनदेन की संख्या करीब 1,860 थी। वर्ष 2023 में भारत ने वैश्विक रीयल-टाइम लेनदेन का 49 फीसदी हासिल किया। जिसमें 46 करोड़ लोग और 6.5 करोड़ व्यापारी यूपीआई का उपयोग कर रहे थे। निस्संदेह, शासन के विभिन्न क्षेत्रों में भी डिजिटल उपयोग में खासी प्रगति हुई है। जिससे व्यवस्था अधिक पारदर्शी और नागरिकों के हितों के अनुकूल हो गई है। इस डिजिटल क्रांति के चलते स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बैंकिंग और अन्य सेवाओं तक नागरिकों की पहुंच आसान हुई है। डिजिटल क्रांति से जुड़ी तमाम चुनौतियों के अलावा अभी देश में डिजिटल डिवाइड की समस्या बनी हुई है। जिसे यथाशीघ्र पाटने की जरूरत है। हालांकि, इस दिशा में आशातीत प्रगति भी हुई है, लेकिन अभी इस दिशा में बहुत कुछ करने के लिये चरणबद्ध प्रयासों की सख्त जरूरत है। यह चुनौती ग्रामीण भारत में अधिक नजर आती है। जहां इंटरनेट सेवाओं और मोबाइलों की पहुंच शहरों के मुकाबले कम है। जाहिर है, जब देश के हर व्यक्ति तक डिजिटल क्रांति का लाभ पूरी तरह नहीं पहुंच पाएगा, इस क्रांति के लक्ष्य अधूरे ही रहेंगे।

निश्चित रूप से देश में स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग आदि सेवाओं में जो व्यापक सुधार आया है, उसका लाभ हर नागरिक तक पहुंचना जरूरी है। वहीं दूसरी ओर देश में डिजिटल डिवाइड की खाई को पाटने की दिशा में मिशन के रूप में प्रयास जारी हैं। लेकिन हाल में हुए कुछ सर्वेक्षणों के निष्कर्ष चिंता बढ़ाने वाले हैं। इसमें शामिल व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण - दूरसंचार, 2025 का उल्लेख करना जरूरी हो जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के केवल 57.2 फीसदी स्कूलों में कार्यात्मक कंप्यूटर ही उपलब्ध हैं। वहीं दूसरी ओर 53.9 प्रतिशत स्कूलों में ही इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। देश के विपक्षी दल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भारत नेट परियोजना के तहत कुल 6.55 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिये लक्षित किया जाना था, लेकिन अभी तक उसमें दो-तिहाई गांवों को कवर किया जाना अभी बाकी है। वहीं दूसरी ओर देश की इस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी ने बीएसएनएल की दुर्दशा को भी उजागर किया है, जो एक के बाद एक पुनरुद्धार पैकेज मिलने के बावजूद टेलीकॉम क्षेत्र की निजी कंपनियों के खिलाड़ियों से पीछे है। निस्संदेह, मोदी सरकार के पास डिजिटल इंडिया की प्रगति के लिये अपनी पीठ थपथपाने के लिये कई कारण हैं, लेकिन उसे कमियों और अंतरालों पर ध्यान देने की सलाह दी जाएगी। निश्चित रूप से डिजिटल पारिस्थितिकीय तंत्र के भीतर व्याप्त असमानताओं को दूर किए बिना विकसित भारत के लक्ष्य हासिल करना है।

बड़े धार्मिक आयोजनों का वैज्ञानिक प्रबंधन जरूरी

विश्वनाथ सचदेव

त्रिभाषा फार्मूले का विरोध करने वालों को भी यह समझना होगा कि आवश्यकता इसके ईमानदार क्रियान्वयन की है। वर्ष 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा-नीति में इस फार्मूले को स्वीकारा गया था। तब यह कहा गया था कि तीसरी भाषा के रूप में उत्तर वाले दक्षिण की किसी भाषा को सीखेंगे और दक्षिण वाले उत्तर की भाषा हिंदी को। पर उत्तर वालों ने यहां ईमानदारी नहीं दिखाई। उन्होंने तीसरी भाषा के रूप में दक्षिण भारत की किसी भाषा के बजाय मुख्यत: संस्कृत को चुना।

आपातकाल में हमारे संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द जोड़े गये थे- पहला 'पंथ निरपेक्षता' और दूसरा समाजवाद। संविधान जब तैयार किया जा रहा था तब भी इन शब्दों की आवश्यकता की चर्चा हुई थी, पर तब हमारे संविधान निर्माताओं ने यह माना था कि यह दोनों विचार संविधान में अन्यत्र स्पष्ट रूप से जुड़े हुए हैं, अत: इन्हें अलग से प्रस्तावना में जोड़ना आवश्यक नहीं है। जब आपातकाल के दौरान इन्हें जोड़ा गया तो तर्क यह दिया गया था कि यह दोनों विचार प्रमुखता के साथ रेखांकित होने चाहिए। संविधान के 42वें संशोधन से इसे रेखांकित कर दिया गया।

बाद की जनता पार्टी की सरकार ने भी इस बात को मान लिया। पचास साल बाद यह विवाद फिर सिर उठा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को यह लग रहा है कि इन दोनों शब्दों को प्रस्तावना से हटा कर अब अपनी विचारधारा को संविधान में शामिल किया जा सकता है। और यदि संख्या की दृष्टि से फिलहाल संविधान में प्रयुक्त संशोधन नहीं हो सकता तो भी देश में अपने विचार के समर्थन में वातावरण बनाने का यह अच्छा मौका है।

ऐसी ही एक कोशिश महाराष्ट्र में भी हो रही है- राज्य की भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्र की नयी शिक्षा-नीति को लागू करने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए यह निर्णय लिया था कि राज्य में त्रिभाषा फार्मूले को लागू किया जाये। इस फार्मूले के अनुसार राज्य के स्कूलों में पहली से पांचवीं कक्षा तक के बच्चों को मराठी और अंग्रेजी के अलावा तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाई जानी थी। विपक्ष, विशेषकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को, सरकार के इस निर्णय का विरोध करके अपनी जमीन को मज़बूत करने का अवसर दिखाई दिया। उद्धव ठाकरे ने घोषणा कर दी कि उनकी पार्टी इस निर्णय को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देगी। लगभग दो दशक पहले बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना को छोड़कर अपना स्वयं का राजनीतिक दल बनाने वाले उनके भतीजे राज ठाकरे को भी इस स्थिति में एक अवसर दिखाई दिया और उन्होंने भी घोषणा कर दी कि राज्य सरकार की ‘मराठी विरोधी नीति’ को लागू नहीं होने दिया जायेगा। कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी भी ठाकरे बंधुओं के आह्वान के साथ जुड़ गयीं। एक बार फिर राज्य में मराठी अस्मिता के नाम पर माहौल बनने लगा। स्थिति को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि पहली से पांचवीं तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी अनिवार्य रूप से नहीं पढ़ाई जायेगी, यदि बच्चे किसी अन्य भाषा को पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए स्कूलों में इसकी व्यवस्था की जायेगी, बशर्ते किसी अन्य भाषा को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम से कम बीस हो। सरकार को लगा था कि इस घोषणा से स्थिति संभल जायेगी। पर ऐसा हुआ नहीं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना (उबाठे) और राज ठाकरे की मनसे, दोनों किसी भी कीमत पर इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। तय हुआ कि पांच जुलाई को राज्य का समूचा विपक्ष मराठी भाषा और मराठी अस्मिता की रक्षा के नाम पर केंद्र के निर्देश से काम करने वाली महाराष्ट्र सरकार के निर्णय के विरोध में आंदोलन करेगा।बाजी हाथ से निकलते देख कर राज्य सरकार ने हिंदी की पढ़ाई वाला अपना कदम वापस लेने का निर्णय किया। अब एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गयी है जो राज्य के स्कूलों में त्रिभाषा फार्मूले को लागू किये जाने के बारे में अध्ययन करके अपना सुझाव देगी।

पहाड़ों की संवेदनशीलता को समझना भी जरूरी

हिमाचल में जल-रौद्र

पंकज चतुर्वेदी

गंभीरता से देखें तो इन आपदाओं को बुलाने में इन्सान की भूमिका भी कम नहीं है। दुनियाभर के शोध कह रहे थे कि हिमालय पर्वत जैसे युवा पहाड़ पर पानी को रोकने, जलाशय बनाने और सुरंगें बनाने के लिए विस्फोटक के इस्तेमाल के अंजाम अच्छे नहीं होंगे।

सुंदर, शांत, सुरम्य हिमाचल प्रदेश में इन दिनों कुदरत ने रौद्र रूप धारण किया है। छोटे से राज्य का बड़ा हिस्सा अचानक आई तेज बरसात और जमीन खिसकने से त्रस्त है तो जहां आपदा आई नहीं वहां के लोग भी आशंका में जी रहे हैं। आषाढ़ में मानसून की पहली बौछार के साथ ही कई जिलों, विशेषकर कुल्लू और धर्मशाला में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। इससे कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। कुल्लू और धर्मशाला जिलों में अनेक जगह बादल फटने की घटनाएं हुईं, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है और अनेक लापता हैं। पिछले एक हफ्ते में कम से कम 30 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कांगड़ा के खनियारा क्षेत्र में इंदिरा हाइड्रो प्रोजेक्ट के पास प्लैश फ्लड में 20 मजदूर बह गए, जिनमें से कुछ के शव बरामद हुए हैं, बाकी की तलाश जारी है।

कुल्लू की सेंज घाटी में तमाम पर्यटक फंसे हुए हैं। यहां बादल फटने से एक ही परिवार के तीन लोग बह गए। धर्मशाला-चतरो-गगल मार्ग और अपर शिमला क्षेत्र में त्यूणी-हाटकोटी मार्ग जैसे कई प्रमुख मार्ग भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अभी तो सावन-भादों आगे हैं। दुखद यह कि वैज्ञानिकों द्वारा इस बारे में दी गई ढेर सारी चेतावनियां फाइलों में बंद हैं। सरकारी महकमे अपने ढर्रे पर काम कर रहे हैं जबकि पहाड़ जलवायु परिवर्तन के विविध कुप्रभावों से ग्रस्त हैं।इसी साल 14-15 फ़रवरी को आईआईटी, बॉम्बे में सम्पन्न दूसरे इंडियन क्रायोस्फीयर मीट में आईआईटी रोपड़ के वैज्ञानिकों ने एक शोधपत्र प्रस्तुत कर बताया था कि हिमाचल राज्य का 45 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा बाढ़, भूस्खलन और हिमस्खलन जैसी आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। 5.9 डिग्री और 16.4 डिग्री के बीच औसत ढलान वाले और 1,600 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र विशेष रूप से भूस्खलन और बाढ़ दोनों के लिए प्रवण हैं। इस बैठक में दुनियाभर के लगभग 80 ग्लेशियोलॉजिस्ट, शोधकर्ता और वैज्ञानिक शामिल हुए। इतनी स्पष्ट चेतावनी के बावजूद न समाज चेता और न ही सरकार।नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, इसरो द्वारा तैयार देश के भूस्खलन नक्शे में हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों को बेहद संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। देश के कुल 147 ऐसे जिलों में संवेदनशीलता की दृष्टि से मंडी को 16वें स्थान पर रखा गया है। यह आंकड़ा और चेतावनी फाइल में सिसकती रह गई।

यही हाल शिमला का हुआ जिसका स्थान इस सूची में 61वें नम्बर पर दर्ज है। प्रदेश में 17,120 स्थान भूस्खलन संभावित क्षेत्र अंकित हैं, जिनमें से 675 बेहद संवेदनशील मूलभूत सुविधाओं और घनी आबादी के करीब हैं। भूस्खलन की दृष्टि से किन्नौर जिला को सबसे खतरनाक माना जाता है। बीते साल भी किन्नौर के बटसेरी और न्यूगलसरी में दो हादसों में ही 38 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद किन्नौर जिला में भूस्खलन को लेकर भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के विशेषज्ञों के साथ-साथ आईआईटी, मंडी व रुड़की के विशेषज्ञों ने अध्ययन किया है।हिमाचल सरकार की डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल द्वारा प्रकाशित एक 'लैंडस्लाइड हैज़ार्ड रिस्क असेसमेंट' अध्ययन ने पाया कि बड़ी संख्या में हाइड्रोपावर स्थल पर धरती खिसकने का खतरा है। लगभग 10 ऐसे मेगा हाइड्रोपावर प्लांट, स्थल मध्यम और उच्च जोखिम वाले भूस्खलन क्षेत्रों में स्थित हैं।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से सर्वेक्षण कर भूस्खलन संभावित 675 स्थल चिन्हित किए हैं।

SWACHH SURVEKSHAN
#Mera Shahar, Meri Pehchan 2023

श्री ए० के० शर्मा, नगर विकास मंत्री

श्रीमती प्रमिला पाण्डेय, महापौर

नगर निगम कानपुर

आइए! मिलकर स्वच्छता के प्रति कदम बढ़ाए, अपने कानपुर नगर को स्वच्छ बनाएं।

नगर की सफ़ाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में हमे चाहिए आपका सहयोग। इसी क्रम में हम आपसे अपील करते है कि

- अपने घर के कूड़े को प्रथक-प्रथक करके नगर निगम द्वारा संचालित डोर टू डोर कूड़ा गाड़ी में ही डालें।
- सड़क पर कूड़ा न फेंके।
- आस पास साफ सफाई रखें, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें।
- प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करें।
- Reduse, Reuse, Recycle की अवधारणा को अपने जीवन में आदत के रूप में ढालें।
- कानपुर नगर को साफ व स्वच्छ बनाने में कानपुर नगर निगम का सहयोग करें।

/KANPUR MUNICIPAL CORPORATION

श्री सुधीर कुमार (आईएएस) नगर आयुक्त

कानपुर सेंट्रल पर विशेष टिकट चेकिंग अभियान शुरू

» अवैध वेंडरों पर गिरी गाज, 91,730 का जुर्माना वसूला

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। यात्रियों को सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रयागराज मंडल द्वारा कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर 2 से 8 सितम्बर तक विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (कोचिंग) हिमांशु शुक्ला के निर्देशन एवं उप मुख्य यातायात प्रबंधक (कानपुर) आशुतोष सिंह के मार्गदर्शन में यह अभियान संचालित हुआ। इसके लिए छह कर्मचारियों की टीम को शिफ्टवार चौबीसों घंटे तैनात किया गया।अभियान के दौरान यात्रियों की सुविधाओं का गहन निरीक्षण किया गया तथा 174 यात्रियों से प्रत्यक्ष फीडबैक लिया गया। रेल अधिकारियों ने खानपान की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं यात्रियों की मूलभूत आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया।

चेकिंग के दौरान ओवर चार्जिंग के छह मामले पकड़े गए। वहीं 36 अवैध वेंडरों को स्टेशन एवं ट्रेनों में खाद्य सामग्री बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जिन्हें आगे की कार्रवाई हेतु जीआरपी के सुपुर्द किया गया। खानपान स्टॉलों पर पाई गई अनियमितताओं पर भी जुर्माना लगाया

गया।साथ ही, बिना टिकट एवं अनियमित यात्रा करने वाले यात्रियों तथा गंदगी फैलाने वालों से कुल 91,730 का जुर्माना वसूला गया।रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें, कचरा केवल डस्टबिन में डालें और सदैव वैध टिकट के साथ यात्रा करें।

राजेपुर में धार्मिक स्थल का झंडा हटाने से तनाव, तीन घायल

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

बिल्हौर(कानपुर)। राजेपुर गांव सोमवार रात अचानक गहमागहमी का केंद्र बन गया। धार्मिक स्थल पर लगे झंडे को हटाने को लेकर शुरू हुई छोटी सी तकरार कुछ ही देर में मारपीट में बदल गई। घटना में तीन लोग चोटिल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए हैलट अस्पताल भेजा गया है।गांव वालों के मुताबिक, हजरत सईद मर्द शाह के धार्मिक स्थल पर बारावफात पर सजावट हुई थी। रात में कुछ युवक पहुंचे और झंडा खींच दिया।

वहां मौजूद लोगों ने टोका तो बहस छिड़ गई। इस दौरान गाली-गलौज और हाथापाई तक की नौबत आ गई।झगड़े में खेत की ओर जा रहे मोनू कटियार, करन कश्यप और अमर कश्यप घायल हुए। उनके परिवार का कहना है कि करीब दर्जन भर से ज्यादा लोग हमला करने आए थे। मारपीट के बाद हमलावर धमकी देकर भाग निकले। पुलिस ने मोनू कटियार की शिकायत पर राजन, लल्ला उर्फ नबाब हुसैन, गोलू उर्फ गुलफाम और वसी समेत 15 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली प्रभारी अशोक सरोज ने बताया कि गांव में अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है और हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं।

कानपुर में बॉलीवुड के Jolly LLB की एंट्री, स्थानीय वकीलों से की मुलाकात

» अक्षय कुमार ने पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार सहित कई अन्य लोगों से की मुलाकात

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। बॉलीवुड की बहुचर्चित फिल्म जॉली एलएलबी-3 का रंग अब कानपुर में भी देखने को मिला। बुधवार 10 सितम्बर को कानपुर एयरपोर्ट पर फिल्म के मुख्य कलाकार अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला का गर्मजोशी से स्वागत किया गया।पुलिस आयुक्त अखिल कुमार, बार एसोसिएशन कानपुर के अध्यक्ष इन्दीवर बाजपेयी, महामंत्री अमित कुमार, लायर्स एसोसिएशन कानपुर के अध्यक्ष दिनेश वर्मा व महामंत्री राजीव यादव ने एयरपोर्ट पर पहुँचकर कलाकारों का अभिनंदन किया। इस मौके पर उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर आगामी फिल्म की सफलता के लिए शुभकामनाएँ दी गईं।इसी कड़ी में आज शहर के रेव थ्री मॉल में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च और प्रोमोशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कानपुर की मिट्टी में अपनी फिल्म का प्रचार करने पहुँचे कलाकारों ने दर्शकों से रूबरू होकर फिल्म देखने की अपील की।गौरतलब है कि जॉली एलएलबी सीरीज़ का हर पार्ट कोर्टरूम ड्रामा और हल्के-फुल्के हास्य के कारण लोगों के बीच खासा लोकप्रिय रहा है। अब तीसरे भाग को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।

विकसित उत्तर प्रदेश संकल्प बैठक में महिलाओं व युवाओं के सशक्तिकरण पर जोर

» मुख्य अतिथि ने कहा 2047 तक विकसित राज्य बनाने में हर वर्ग की होगी अहम भूमिका

» ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधि और स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने निभाई सक्रिय भागीदारी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। विकासखंड मलासा में मंगलवार को विकसित उत्तर प्रदेश संकल्प बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डीएवी डिग्री कॉलेज कानपुर के पूर्व प्रोफेसर निरंकार प्रसाद तिवारी ने कहा कि महिलाओं और युवाओं को जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना ही 2047 तक उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया यह संकल्प तभी सफल हो सकता है जब समाज का हर वर्ग आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से सक्षम हो। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख स्वतंत्र पासवान ने की।

कार्यक्रम में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, पंचायत सचिव और स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी संजय कन्नौजिया,

मनोज कुमार, सचिव रवि प्रताप सिंह, सचिव ज्योति रत्ना, अर्जुन सिंह, अमरेश कुमार, छत्र पाल, संदीप निषाद, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रामू संखवार, हमीद, लालू सचान, त्रिलोकी नाथ, धर्मेंद्र सिंह, चंद्रशेखर द्विवेदी, क्षेत्र पंचायत सदस्य

राधा सविता, रुचि त्रिपाठी, निर्मला, सीता, ऊषा देवी, अनीता समेत बड़ी संख्या में गणमान्यजन मौजूद रहे।

यह संकल्प बैठक न केवल ग्राम्य विकास को गति देने वाली पहल साबित हुई, बल्कि महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का भी सशक्त प्रयास रही।

नवरात्र से बेहमई समेत कई मार्गों पर दौड़ेंगी रोडवेज बसें

» अब यात्रियों को नहीं करनी पड़ेगी मशक्कत, सीधे पहुंचेगी बसें गांव-गांव

» कानपुर, लखनऊ और अन्य जनपदों से होगा सीधा संपर्क

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। बेहमई, रसूलाबाद सहित जिले के उन मार्गों पर जहां अब तक रोडवेज बसें नहीं पहुंच पा रही थीं, वहां जल्द ही बस संचालन शुरू किया जाएगा। नवरात्र से रोडवेज विभाग इन रूटों पर बसें चलाने की तैयारी में है।

इन इलाकों के यात्रियों को अब जिला मुख्यालय, अस्पताल और लखनऊ-कानपुर जैसे बड़े शहरों तक पहुंचने के लिए डग्गामार वाहनों या हाइवे पर खड़े होकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा।एआरएम मो. अशफाक ने बताया कि निगम से मिलने वाली 42 सीटर बसों को लंबी दूरी वाले मार्गों पर लगाया जाएगा। इन बसों को बेहमई, रसूलाबाद, पुखरायां, बिल्हौर, मैथा और रनियां होते हुए कानपुर व लखनऊ तक संचालित करने की योजना है। इसके अलावा माती से मलासा, चांदपुर, मूसानगर, घाटमपुर के रास्ते कानपुर और माती से अमरौधा, मंगलपुर व देवराहट होकर लखनऊ तक बसें चलाने की तैयारी है।इन बसों के चलने से दूरस्थ ग्रामीण इलाकों के लोगों को राहत मिलेगी। जिला अस्पताल, तहसील और अन्य जरूरी कार्यों के लिए सफर आसान होगा। इसके अलावा लखनऊ, फतेहपुर और इटावा जैसे जनपदों तक भी सीधे बसें मिलेंगी। लंबे समय से बसेरा बना इंतजार अब खत्म होने जा रहा है और यात्रियों को सुविधाजनक व सुरक्षित यातायात उपलब्ध होगा।

डॉक्टर का अधिकारियों के प्रति अभद्र व्यवहार - प्रशासन की ढीली कार्रवाई पर उठे सवाल

» स्वराज इंडिया संवाददाता

कानपुर देहात। राजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अमित निरंजन का घमंडी और अभद्र रवैया एक बार फिर चर्चा में है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एसडीएम और तहसीलदार जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को कुर्सी तक न देने की हद पार कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने अधिकारियों को स्टूल पर बैठने को कहा और स्टाफ के साथ भी दुर्व्यवहार किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें डॉक्टर निरंजन खुलेआम यह कहते सुने जा सकते हैं कि वह अपनी शर्तों पर ही काम करेंगे।जिलाधिकारी कपिल सिंह ने मामले की गोपनीय जांच के आदेश जरूर दिए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने पूरे प्रकरण को हल्के में निपटा दिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने इस घोर अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई करने के बजाय मात्र डॉक्टर का तबादला राजपुर पीएचसी से हवासपुर सीएचसी कर दिया।यानी अधिकारियों का अपमान करने वाले डॉक्टर को विभाग ने सजा नहीं बल्कि तबादले का तोहफा दे दिया। यह ढीली कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली और योगी सरकार के अफसरशाही तंत्र पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है।डॉक्टर निरंजन की यह धमकी किजहां भी रहूंगा, अपनी शर्तों पर ही काम करूंगा अब प्रशासन की साख पर सीधा हमला मानी जा रही है। सवाल उठता है कि क्या सरकार ऐसे बेलगाम अधिकारियों को संरक्षण दे रही है?

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। संपादकः अनूप कुमार RNI No.: UPHIN/2023/86769 | Email: swarajindia2023@gmail.com | Mob: 7800009853, | Website: www.swarajindianews.com | (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

बिना मान्यता के स्कूलों पर शिक्षा विभाग की मेहरबानी

» झोपड़पट्टी और दुकानों में चल रहे स्कूल, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़

बीएसए ऑफिस की चुप्पी से बढ़ रहा भ्रष्टाचार और सवालों का अंबार

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही बिना मान्यता वाले विद्यालयों को बंद करने के निर्देश लगातार जारी कर रही हो, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों की ढिलाई और मनमानी से विकास खण्ड मलासा के अंतर्गत तुर्कीमऊ गांव में गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल बेखौफ तरीके से संचालित हो रहे हैं। साल दर साल इन स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि विभागीय अधिकारी सबकुछ जानते हुए भी चुप्पी साधे हुए हैं।

कहीं एक कमरे में तो कहीं झोपड़पट्टी में प्राथमिक स्तर तक के स्कूल चल रहे हैं, जहां कम पढ़े-लिखे बेरोजगार युवकों को बेहद कम पैसे में शिक्षक बना दिया जाता है।गांव-गांव में शिक्षा सत्र की शुरुआत होते ही नए स्कूल खोलने की होड़ लग जाती है। मानक और मान्यता की परवाह किए बिना लोग मकानों, दुकानों और झोपड़ियों तक में बच्चों की शिक्षा का खेल शुरू कर देते हैं। यहां तक कि कोचिंग का रजिस्ट्रेशन करवाकर भी स्कूल खोले जा रहे हैं। हर साल शिक्षा विभाग की ओर से ऐसे स्कूलों को बंद कराने की घोषणा की जाती है, मगर वास्तविकता इसके उलट होती है। गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ रही है, जिससे विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।सूत्रों के मुताबिक, हाल ही में बीएसए ने इस क्षेत्र का औचक निरीक्षण भी किया था और उन्हें इन अवैध स्कूलों की जानकारी मिली थी। बावजूद इसके, कार्रवाई से अफसर कतराते दिख रहे हैं।इस मामले पर बीएसए अजय मिश्रा ने बताया कि संबंधित स्कूल को नोटिस भेजा जा चुका है। लेकिन जैसे ही आगे की कार्रवाई के सवाल उठे, उन्होंने फोन काट दिया।

बिना मान्यता के धड़ल्ले से चल रहे स्कूल, शिक्षा विभाग बना मूकदर्शक

» नोटिस के बाद भी नहीं थमा संचालन

» मलासा ब्लॉक के टीएस पब्लिक स्कूल समेत दर्जनों पर कार्रवाई ठप

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। शासन के सख्त आदेशों के बावजूद जनपद में बिना मान्यता के संचालित हो रहे स्कूलों पर कार्रवाई ठप है। शिक्षा विभाग के अधिकारी केवल नोटिस जारी कर औपचारिकता निभा रहे हैं, जबकि स्कूल संचालक नोटिस को हवा में उड़ाकर विद्यालयों का संचालन खुलेआम कर रहे हैं।

सबसे बड़ा मामला विकास खंड मलासा के तुर्किमऊ गांव स्थित टीएस पब्लिक स्कूल का है, जो बिना मान्यता के वर्षों से चल रहा है। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक भी बार-बार लिखित शिकायत कर चुके हैं कि इन अवैध स्कूलों की वजह से सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या नहीं बढ़ पा रही है। इसके बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग की चुप्पी सवाल खड़े कर रही है।

शासन के आदेश कागजों तक सीमित

शासन की ओर से स्पष्ट निर्देश है कि बिना मान्यता के संचालित विद्यालयों पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया जाए और नोटिस के बाद भी संचालन जारी रहने पर 10 हजार रुपये प्रतिदिन का अर्थदंड वसूला जाए। लेकिन कानपुर देहात में यह आदेश कागजों तक सीमित है।स्वराज इंडिया की पड़ताल में सामने आया कि जनपद के विभिन्न ब्लॉकों में दर्जनों स्कूल बिना मानक पूरे किए संचालित हो रहे हैं। इन स्कूलों में अप्रशिक्षित शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता लगातार प्रभावित हो रही है।जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजय कुमार मिश्रा ने मामले में कहा गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालन की जानकारी नहीं थी। जांच कराई जाएगी और हर हाल में ऐसे स्कूल बंद कराए जाएंगे।

कानपुर देहात में युवक फांसी पर झूला

» फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। रूरा थाना क्षेत्र के भारापुरवा गांव में मंगलवार देर शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई। 32 वर्षीय अजीत सिंह ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।घटना की जानकारी मिलते ही चौकी प्रभारी एसआई रजनीश कुमार वर्मा टीम के साथ मौके पर पहुंचे और अजीत को एंबुलेंस द्वारा रूरा सीएचसी भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और जांच में सहयोग किया।अजीत की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस का कहना है कि आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अयोध्या : नगर निगम में टेंडर ठगी का बड़ा खेल उजागर

» पूर्व कांग्रेसी आरिफ आब्दी समेत तीन पर 47 लाख हड़पने का आरोप

» फर्जी वर्क ऑर्डर से रची साजिश

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या।नगर निगम के टेंडर में साझेदारी का लालच देकर अयोध्या में एक बड़ा ठगी कांड सामने आया है। शहर एक बड़े जनप्रतिनिधि के करीबी बताए जा रहे आरिफ आब्दी समेत तीन लोगों पर 47 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगा है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मुख्य आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

बताते चले कि प्रमोदवन निवासी देव नारायण

आरोपी आरिफ आब्दी

त्रिपाठी ने एफआईआर में आरोप लगाया कि उनके बेटे अभिनव के अस्पताल पर गोंडा निवासी सुभाष सिंह और देवकाली के रिंकू मौर्या, अपने साथ शहर के राठ हवेली, बड़ा इमामबाड़ा निवासी आरिफ आब्दी को लेकर आए। इन लोगों ने नगर निगम में ऊंचे रसूख का हवाला देते हुए कहा कि वे सोलर लाइट लगाने और कूड़ा उठवाने जैसे करोड़ों के ठेके दिलवा सकते हैं।

नेता जी से नजदीकी पर सवाल

सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने पुष्टि की कि तीनों आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया गया है और आरिफ आब्दी से पूछताछ की जा रही है। दिलचस्प यह है कि आरिफ आब्दी और नेता जी का पुराना कांग्रेस कनेक्शन रहा है। सोशल मीडिया पर दोनों की दर्जनों तस्वीरें मौजूद हैं 13 मई को नेता जी के साथ केक काटते हुए, ईद के मौके पर, उनके घर और इमामबाड़ा में।यह मामला केवल ठगी का नहीं, बल्कि नगर निगम की विश्वसनीयता, राजनीतिक रिश्तों और सफेदपोश अपराध की गहराई को उजागर करता है।

फोटो से बढ़ी विश्वसनीयता

तीनों ने अधिकारियों और नेताओं के साथ खिंचवाई तस्वीरें दिखाकर पीड़ित को भरोसे में लिया। आरिफ आब्दी ने 13.65 करोड़ रुपये के सोलर लाइट टेंडर का हवाला देते हुए पार्टनरशिप का प्रस्ताव रखा।

किस्तों में पैसा लगाने की बात पर सहमति बनी और दिसंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच 42 लाख रुपये बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए। इसके अलावा सामान और लेबर के नाम पर 5.95 लाख रुपये नगद व यूपीआई से दिए गए।

टेंडर की गारंटी के तौर पर देवांश फार्मा (पीड़ित के बेटे की फर्म) के चार ब्लैंक चेक भी ले लिए गए। ठगी को पुख्ता दिखाने के लिए फर्जी ईमेल आईडी से वर्क ऑर्डर भेजा गया और उस पर अधिकारियों के हस्ताक्षर युक्त नकली दस्तावेज भी दिखाए गए।

जब आरोपी कॉल रिसीव करना बंद कर दिए तो त्रिपाठी को शक हुआ।

नगर निगम से पड़ताल में खुलासा हुआ कि ऐसा कोई टेंडर जारी ही नहीं हुआ है और सारे मुहर व हस्ताक्षर फर्जी हैं।

अवध विश्वविद्यालय का स्थायी निवास घोटाला

ट्रांसफर आदेश कागज़ पर, प्रभारी वहीं के वहीं!

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। डॉ राममनोहर लोहिया विश्वविद्यालय का नाम सुनते ही दिमाग में पढ़ाई, शोध और ज्ञान का केंद्र आता है, लेकिन हकीकत कहीं ज़्यादा क्राइम स्टोरी जैसी है। यहाँ विभागीय कुर्सियाँ बदलती नहीं, बल्कि स्थायी रूप से जमी रहती हैं। नियम-कायदों की किताबें धूल फांकती हैं और प्रभारी नामक पदाधिकारी सालों-साल तक उसी विभाग पर कब्ज़ा जमाए रहते हैं।

विश्वस्त सूत्रों की माने तो परीक्षा विभाग का हाल तो ऐसा है जैसे निजी जागीर हो। प्रभारी राजेश पांडे जी लगातार 10 वर्षों से वहीं जमे हुए हैं। प्रमोशन भी यहीं से, प्रभारी भी यहीं। छात्रों की पीढ़ी बदल गई, कुलपति बदल गए, लेकिन परीक्षा विभाग का प्रभारी वही पुराना चेहरा। हरीश और राजीव जैसे नाम भी इसी खेल के हिस्सेदार हैं। बरसों से वहीं टिके हैं। संजीव श्रीवास्तव, सीमा तिवारी और सुरेन्द्र शर्मा का भी यही हाल। ट्रांसफर का आदेश आया भी तो बस दिखावे के लिए क्योंकि असलियत में सब वहीं पर थे और आज भी वहीं हैं।

सूत्र बताते है कि गोपनीय विभाग की कहानी तो और भी चौंकाने वाली है। यहाँ अनूप सिंह रिटायर होने के बाद भी सेवा विस्तार पाकर अब तक प्रभारी बने बैठे हैं। यह नियम किस किताब से निकला, यह किसी को पता नहीं। बाल कुमार, अनिल गौतम और अनिल शर्मा ये सब ट्रांसफर होकर भी वापस बुला लिए गए वाली श्रेणी में आते हैं। जैसे विभाग बिना इनके चल ही नहीं सकता।सबसे बड़ा सवाल यह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इन खेलों पर चुप क्यों है? क्या विभाग चलाने के लिए सिर्फ यही लोग बचे हैं? क्या ट्रांसफर आदेश सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है, जिसे चहेतों की मज़ी से फाड़ा और जोड़ा जाता है? क्या यहाँ कुर्सियाँ भी आजन्म आरक्षण पर दी जाती हैं?अगर नियम किताब में कुछ और कहते हैं और ज़मीन पर कुछ और चल रहा है, तो यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि साफ-साफ अपराध है। विभागीय प्रभारी की कुर्सियाँ अब प्रभावशाली चेहरों की पकड़ में हैं और कोई भी नया चेहरा यहाँ कदम नहीं रख सकता है। साफ है विश्वविद्यालय अब शिक्षा का मंदिर नहीं, बल्कि स्थायी निवास घोटाले का गढ़ बन चुका है। जहाँ छात्र डिग्री लेने आते हैं और अधिकारी स्थायी प्रभारी बनने।

टीईटी अनिवार्य पर शिक्षकों में असमंजस जारी, समाधान की कोशिशें तेज

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

लखनऊ/कानपुर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीईटी (टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट) को सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य किए जाने के आदेश के बाद 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। आदेश के अनुसार, कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को दो वर्ष के भीतर टीईटी पास करना होगा, अन्यथा उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। हालांकि, जिन शिक्षकों की सेवा अवधि केवल पाँच वर्ष शेष है, उन्हें परीक्षा से छूट मिलेगी, लेकिन पदोन्नति के लिए टीईटी पास करना उनके लिए भी जरूरी रहेगा।

यह आदेश उन शिक्षकों के लिए चुनौती बना है जिन्हें नियुक्ति के समय टीईटी अनिवार्य नहीं था। ऐसे कई शिक्षक अब उम्र और पाठ्यक्रम के दबाव के चलते परीक्षा को लेकर चिंतित हैं। मृतक आश्रित, इंटरमीडिएट पास, कम अंक प्रतिशत वाले, डीपीएड-बीपीएड डिग्रीधारी और आयु सीमा पार कर चुके कई शिक्षक तो आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। शिक्षक संघ का मानना है कि

» सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सबसे अधिक प्रभावित हो रहे पुराने शिक्षक

» बड़े आंदोलन की राह तलाश रहे हैं यूपी के प्राइमरी शिक्षक

यदि सरकार नियमों में संशोधन कर दे या कोर्ट शिक्षकों की व्यवहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कोई राहत प्रदान करे, तो हजारों पुराने शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित हो सकती है। आने वाले दिनों में इस विषय पर सरकार और शिक्षक संगठनों के बीच बातचीत तेज होने की संभावना है।

शिक्षक संघ की सक्रियता

इस स्थिति से निपटने के लिए शिक्षक संगठन दो रास्तों पर काम कर रहे हैं—

1. सरकार पर दबाव बनाना कि पुराने शिक्षकों को छूट मिले और उनकी नियुक्ति के समय लागू नियमों के आधार पर ही सेवा शर्तें तय हों।

2. कानूनी विकल्प तलाशना। इसके तहत रिव्यू पिटीशन, आदेश की क्लैरिफिकेशन और समय बढ़ाने जैसी अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने की तैयारी है।

SC-ST एक्ट में फँसाकर आकाश पांडेय का पूरा जीवन किया बर्बाद, कोर्ट में बेगुनाह साबित

» करीब 3 साल जेल में रहने के बाद अब कोर्ट ने उन्हें निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया

» देश के कानूनी सिस्टम से आमजनमानस आज भी बेहाल

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

झांसी।देश की न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। झांसी के आकाश पांडेय को झूठे मुकदमों में फँसाकर जीवन बर्बाद कर दिया गया। करीब 3 साल जेल में रहने के बाद अब कोर्ट ने उन्हें निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया है। इस

पीड़ित आकाश पांडेय

बीच माता-पिता की मौत ने उनके परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया।

मामला 8 जून 2018 का है। मातादीन अहिरवार की बेटी की लाश फांसी के फंदे से लटकी मिली थी। इसके बाद मातादीन अहिरवार ने आकाश पांडेय और उनके ममेरे भाई पर गंभीर आरोप लगाते हुए कोर्ट के आदेश पर छेड़छाड़, आत्महत्या के लिए उकसाने, SC-ST एक्ट और पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कराई।आकाश पांडेय को जेल भेज दिया गया और वे पूरे 3 साल तक सलाखों के पीछे रहे। उनका ममेरे भाई एक साल बाद जमानत पर छूट गया। लंबे ट्रायल के दौरान आकाश के माता-पिता ने बेटे का दर्द सहन नहीं कर पाए और दोनों की मृत्यु हो गई।

अब अदालत ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आकाश पांडेय और उनके भाई को बरी कर दिया। कोर्ट ने पाया कि लड़की की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। जांच में पीड़िता के पिता मातादीन अहिरवार की संलिप्तता सामने आई है, जिसके खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।यह केस दिखाता है कि कैसे कानूनी प्रावधानों के दुरुपयोग से किसी निर्दोष का जीवन बर्बाद किया जा सकता है। 3 साल की जेल, माता-पिता की मौत और समाज में बेगुनाही साबित होने तक उठाए गए सवाल—यह कहानी न्याय व्यवस्था के अंधेरे पहलू को उजागर करती है।स्वराज इंडिया अखबार इस भयावह और दिल दहला देने वाले केस की पूरी डिटेल जल्द प्रकाशित करेगा।

नियम-कानून गरीबों के लिए, रसूक वालों के लिए हो जाते मौन?

» लोकप्रिय हॉस्पिटल का भौकाल, विकास का बवाल

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर विकास का बुलडोज़र गरजता हुआ चला। सैकड़ों घर जमींदोज़, दुकानों की दीवारें ध्वस्त, पेड़ों की जड़ें उखड़ीं। गरीबों के आशियाने ऐसे गिरे मानो ताश के पत्ते। मगर इस मलबे और शोर के बीच एक दीवार अब भी तानाशाह की तरह खड़ी है लोकप्रिय अस्पताल की दीवार।

सवाल सीधा है क्या विकास प्राधिकरण का नियम सिर्फ गरीबों की झोपड़ी और छोटे दुकानदारों के लिए है? क्योंकि जिस अस्पताल की दीवार ने चौड़ी सड़क और फ्लाईओवर को बीच रास्ते में रोका है, वहाँ प्रशासन की मशीनें आरती उतारकर लौट जाती हैं।लोगों की जुबान पर यही चर्चा है ऐसा कौन सा फ्इंजेक्शनफ् चढ़ा है विकास प्राधिकरण पर, जिसके बाद पूरा अमला सुन्न बैठा है। यह कौन सा धर्मार्थ चिकित्सालय है, जिसके गिरने से चिकित्सा सेवा ऐसे धड़ाम हो जाएगी मानो सेंसेक्स मंदी में।

बता दे कि सामने फ्लाईओवर का पहला छोर बन चुका है। दूसरी तरफ चौड़ी सड़क का काम पूरा। मगर बीच में अस्पताल अड़ा है मानो पूरा शहर उसकी धौंस पर सांस ले रहा हो। नाले का निर्माण भी अटका, सड़क का चौड़ीकरण भी ठहरा। लोग कह रहे हैं अगर यह अस्पताल किसी गरीब का मकान होता तो अब तक जेसीबी उस पर राम नाम सत्य गा चुकी होती। विकास प्राधिकरण की जेसीबी गरीब पर गरजती है और बड़े अस्पताल पर डर से रुक जाती है। अयोध्या में विकास का पहिया तेज़ी से घूम रहा है, लेकिन 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर यह पहिया लोकप्रिय अस्पताल के गेट पर पंचर पड़ा है।अब सवाल यह है क्या प्रशासन इस भौकाल को तोड़ पाएगा या फिर विकास की किताब में यह अस्पताल स्थायी फुटनोट बन जाएगा?

» नेपाल में तख्ता पलट से मचा हुआ है कोहराम

» संकट की जड़ जनता का असंतोष बताया जा रहा है

नेपाल में बवाल

नेपाल संकट: क्या भारत समर्थक

सरकार की ओर बढ़ रहा है पड़ोसी?

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली।नेपाल की राजनीति एक बार फिर अस्थिरता की चपेट में है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की वामपंथी सरकार जिस तेजी से जनसमर्थन खो रही है, उससे सत्ता परिवर्तन की आशंका गहरा गई है। इस्तीफ़ों की झड़ी, सड़क पर उतरती नई पीढ़ी और भ्रष्टाचार व दमनकारी नीतियों के खिलाफ बढ़ता आक्रोश इस बात का संकेत है कि नेपाल की सत्ता समीकरण अब बदलने की ओर है।हालिया प्रदर्शनों ने ओली सरकार की नींव हिला दी है।

सोशल मीडिया नियंत्रण, बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर युवाओं ने व्यापक आंदोलन छेड़ा। इस आंदोलन को दबाने के दौरान पुलिस की फायरिंग में 19 लोगों की मौत हो गई।

यही बिंदु सरकार के खिलाफ जनाक्रोश का ट्रिगर बना। इसके बाद ओली कैबिनेट से इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया—गृह मंत्री रमेश लेखक

और कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी जैसे वरिष्ठ नेताओं ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ा।

» आंदोलन को दबाने के दौरान पुलिस की फायरिंग में 19 लोगों की मौत हो गई

ओली बनाम कांग्रेस- सत्ता संघर्ष की अगली बिसात

ओली की पार्टी सीपीएन-यूएमएल संसद की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है, जबकि नेपाली कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। यदि ओली सरकार बहुमत खो देती है, तो कांग्रेस, माओवादी केंद्र और क्षेत्रीय दल मिलकर नया गठबंधन बना सकते हैं। नेपाली कांग्रेस का रुझान लोकतांत्रिक और मध्यमार्गी राजनीति की ओर है, जो परंपरागत रूप से भारत के करीब मानी जाती है। यही वजह है कि मौजूदा संकट को भारत समर्थक ताकतों की वापसी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

भारत और चीन पर क्या असर पड़ेगा ?

नेपाल में सरकार का झुकाव सीधा भारत और चीन की कूटनीतिक स्थिति को प्रभावित करता है।यदि कांग्रेस गठबंधन सत्ता में आता है तो सीमा विवाद, मधेस मुद्दा और पारगमन व्यापार जैसे मसले सहजता से आगे बढ़ सकते हैं। भारत-नेपाल सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्तों को भी प्राथमिकता मिल सकती है। वहीं, ओली की सरकार ने बीजिंग से नजदीकी बढ़ाने और भारत के खिलाफ राष्ट्रवादी भावनाओं को हवा देने की कोशिश की थी। सत्ता परिवर्तन के बाद चीन का यह प्रभाव सीमित हो सकता है। भारत के लिए चुनौती यह होगी कि नेपाल में स्थिरता लाने की कोशिशों के साथ चीन के दबाव और नेपाल की आंतरिक राजनीति में बदलते समीकरणों को संतुलित करना।

नेपाल को लेकर भविष्य का परिदृश्य

नेपाल की मौजूदा अस्थिरता इस बात का संकेत है कि वहां नई पीढ़ी पारंपरिक राजनीति से निराश हो चुकी है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसके केंद्रीय मुद्दे हैं। यदि नई सरकार लोकतांत्रिक और लोककल्याणकारी एजेंडा लेकर आती है, तो भारत-नेपाल रिश्तों में सहजता और सहयोग की संभावना बढ़ेगी। लेकिन बार-बार की उठापटक नेपाल की विकास यात्रा को लंबा खींच सकती है और भारत को अपनी कूटनीति और सुरक्षा रणनीति दोनों मोर्चों पर चौकस रहना होगा।

नेपाल की स्थिरता भारत के लिए क्यों जरूरी?

1. सीमा सुरक्षा- भारत-नेपाल खुली सीमा का साझा करते हैं। राजनीतिक अस्थिरता से सीमाई इलाकों में अवैध गतिविधियों का खतरा बढ़ सकता है।

2. आर्थिक जुड़ाव- बड़ी संख्या में नेपाली नागरिक भारत में काम करते हैं। नेपाल में संकट सीधे तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था और श्रम बाज़ार को प्रभावित करता है।

3. क्षेत्रीय संतुलन- नेपाल की राजनीतिक दिशा से पूरे दक्षिण एशिया में भारत-चीन के सामरिक संतुलन पर असर पड़ता है।